International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 13 Issue 4, July-August, 2025

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. मनीष सैनी[1], अंकिता सैनी[2]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, बियानी गर्ल्स बी. एड. कॉलेज
[2]बी. एड. एम. एड. छात्रा बियानी गर्ल्स बी. एड. कॉलेज

सारांश

शिक्षा यह उसके ज्ञान व कला कौशल में वृद्धि करती है और उसके आचरण–व्यवहार में परिवर्तन परिष्कार करती है। यही उसे एक देश का सुसभ्य, सुयोग्य नागरिक, एक समाज का उपयोगी जिम्मेदार सदस्य बनाती है। सीखने–सिखाने की यह सप्रयोजन चैतन्य, गतयात्मक, सामाजिक प्रक्रिया समाज में अनवरत रूप से चलती रहती है। इसी के आधार पर कोई समाज नित नए आयाम स्थापित करता है और अपनी सभ्यता, संस्कृति का विकास, संरक्षण, परिष्कार हस्तांतरण करता है। आज की चकाचौंध भरी सभ्य दुनिया के पीछे एकमात्र तत्व निहित है वह शिक्षा ही है। इसी शिक्षा के बल पर मानव ने महासागर की अथाह गहराई को नाप लिया है। धरती का सीना चीरकर विविध खनिज संसाधनों का दोहन कर रहा है और अनंत अथाह अंतरिक्ष में गोते लगाकर अपने ज्ञान भण्डार में दिनों–दिन वृद्धि करता जा रहा है। स्पष्ट है शिक्षा मानव सभ्यता के विकास का मेरूदण्ड है। यह मेरूदण्ड परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य, धर्म जैसे अभिकरणों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है।धरती पर मानव के उदय के साथ ही शिक्षा का इतिहास शुरू होता है, जब आदि मानव अपनी शारीरिक सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति और अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना शुरू करता है तो एक तरह से उसको शिक्षा–प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। उस समय यह प्रक्रिया काफी सरल रहती है।

शब्दावलीः–शिक्षा, निजीकरण, माध्यमिक शिक्षा

प्रस्तावना

मानव अनुभवों में वृद्धि और समूह समाज की उत्पत्ति के साथ यह प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में विशेष व्यक्तियों द्वारा विशेष स्थानों पर शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने अपने को केवल उच्च शिक्षा तक सीमित रखा और यह उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा थी।किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए निजीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

बनती है और रोजगार पैदा होता है। यह व्यवस्था, ग्राहक सेवाओं और वस्तुओं के मानक में सुधार करके लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करता है। चलिए आज इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि निजीकरण क्या है और क्या अर्थव्यवस्था के लिए निजीकरण जरुरी है ?निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। यानि निजीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक संस्थान और इकाइयों को निजी क्षेत्र मे स्थानांतरित किया जाता है।

यहाँ पर स्थानांतरित करने का अर्थ है कि स्वामित्व सरकार के हाथों से निकल कर निजी व्यक्तियों या समूहों के हाथ मे आ जाता है। निजीकरण से आशय ऐसी औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किये जाने से है जो अभी तक सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में थी।

निजीकरण के समर्थकों का कहना है कि निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देती है, जो अंततः बेहतर सेवा और उत्पाद, कम कीमत और कम भ्रष्टाचार उत्पन्न करती है। निजी शब्द का अर्थ होता है व्यक्तिगत अर्थात जो सार्वजनिक परिधि से बाहर हो। निजी क्षेत्र मे ऐसी इकाइयां, संस्थान या उद्योग आते हैं जिनमे मालिकाना हक़ किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का होता है। हम कह सकते हैं कि ऐसी इकाइयां, संस्थान या उद्योग जो सार्वजनिक नियंत्रण के बाहर आते हैं उन्हें निजी क्षेत्र कहा जाता है।

समस्या का औचित्य –

आजकल निजीकरण Privatization शब्द का शोर काफी सुनायी दे रहा है। क्योंकि सरकार द्वारा नियंत्रि अधिकतर कंपनियां निजीकरण की राह पर हैं। सरकार सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजीकरण यानी सरकारी कंपनियों को बेचने पर जोर दे रही है। निजीकरण, यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में पिछले कुछ सालों में देश में काफी बहस हो रही है और सबसे ज्यादा विवाद रेलवे और बैंकों के निजीकरण को लेकर रहा है। वैसे निजीकरण को लेकर लोगों के अपने–अपने तर्क हैं। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई इसे गलत। नयी आर्थिक नीति के तहत साल 1991 मे भारतीय अर्थव्यवस्था Indian Economy में कई महत्वपूर्ण सुधार किये गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को देश और विदेश के निजी क्षेत्र के व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। इसकी शोधकर्त्ता ने इस समस्या –***''माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन''*** का चयन किया है।

सम्बन्धित साहित्य

(1) **राय, ए.के. (2025)** इस शोध का उद्धेश्य निजीकरण के रूप में आयु, मूल्य व व्यवहार में पाये जाने वाले संबंध का अध्ययन करना था। निष्कर्ष के रूप में पाया कि निजीकरण व मूल्यों में 15, 17, 19 वर्ष की आयु में उतार–चढ़ाव आता है। 17 वर्ष में आने पर छात्र के व्यवहार में अच्छा प्रदर्शन दिखाई देता है।

(2) **डागोर, बी.एस. (2025)** इस अध्ययन का उद्धेश्य महाविद्यालयी स्तर पर छात्र–छात्राओं में व्यक्तित्व संबंधी चिन्ता व निजीकरण के मध्य संबंध का अध्ययन करना था। निष्कर्ष रूप में पाया कि साइयोजिस्ट व अमितव्ययता का चिन्ता के साथ सीधा संबंध था। अर्न्तमुखी विद्यार्थियों की अपेक्षा बर्हिमुखी विद्यार्थियों में निजीकरण की लोचशीलता तथा प्रवाहगम्यता अधिक पाई गई, लिंग के आधार पर निजीकरणत्मक प्रवाहगम्यता का स्तर प्रभावित होता है।

(3) **कुमारी अरूणा (2024)** इस अध्ययन का मुख्य उद्धेश्य हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों में अध्ययरत खिलाड़ी व गैर खिलाड़ी छात्राओं के निजीकरणत्मक चिन्तन, समायोजन तथा आत्म–संप्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन कार्य करना था। निष्कर्ष के रूप में पाया कि खिलाड़ी छात्राएं जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित थी, भावनात्मक रूप से सामाजिक तथा शहरी समायोजन में गैर खिलाड़ी छात्राओं से अधिक समायोजित पाई गई। गैर खिलाड़ी छात्राओं ने खिलाड़ी छात्राओं की अपेक्षा सभी प्रकार के निजीकरणत्मक चिन्तन के चरों में अधिक अंक प्राप्त किये।

(4) **रवैन्गटे, वी. (2024)** इस अध्ययन का मुख्य उद्धेश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास का निजीकरण से संबंध का अध्ययन करना था। निष्कर्ष रूप में पाया कि उच्च निजीकरण छात्रों में निम्न निजीकरणत्मक छात्रों की अपेक्षा विश्लेष्णात्मक सोच, निश्चयात्मकता, भावों से प्रभावित होना, परिचायक बुद्धि अधिक होती है। संवेदनशीलता बौद्धिक स्तर स्वतंत्रता या स्वावलम्बन जिम्मेदारी के अहसास का निजीकरणत्मक सोच के साथ सहसंबंध पाया गया। ग्रामीण निजीकरणत्मक छात्रों की अपेक्षा शहरी उच्च निजीकरण छात्राओं में संवेगात्मक स्थिरता आत्म संतुष्टि तथा बौद्धिक स्तर जागरूकता की मात्रा अधिक पाई गई।

(5) **जोन, सी.डी. (2023)** इस अध्ययन का उद्धेश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिंग और प्रभाव का अध्ययन करना था। निष्कर्ष रूप में पाया कि शाब्दिक एवं सम्पूर्ण निजीकरण लघु या छोटे परिवारों के बच्चों में बड़े परिवारों के बच्चों की अपेक्षा अधिक थी, जबकि अशाब्दिक निजीकरण पर परिवार के आकार का कोई प्रभाव नहीं था। अशाब्दिक व सम्पूर्ण निजीकरण वहां उच्च भी जहां छात्र अभिभावक अन्तः क्रिया अधिक थी। जबकि शाब्दिक निजीकरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं था।

साहित्य विवेचना

प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन करना है। इससे सम्बन्धित अध्ययन निम्न है –**राय, ए.के. (2025), डागोर, बी.एस. (2025), कुमारी अरूणा (2024), रवैन्गटे, वी. (2024), जोन, सी.डी. (2023)** अतः उपरोक्त शोध अध्ययनों में निजीकरण Privatization शब्द का शोर काफी सुनायी दे रहा है। क्योंकि सरकार द्वारा नियंत्रित अधिकतर कंपनियां निजीकरण की राह पर हैं। सरकार सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निजीकरण यानी सरकारी कंपनियों को बेचने पर जोर दे रही है। निजीकरण, यह एक ऐसा

विषय है जिसके बारे में पिछले कुछ सालों में देश में काफी बहस हो रही है और सबसे ज्यादा विवाद रेलवे और बैंकों के निजीकरण को लेकर रहा है।

समस्या कथन –

''माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन''।

समस्या का उद्देश्य

(1) माध्यमिक स्तर के सहायता प्राप्त विद्यालयों के संसाधनों का अध्ययन करना।
(2) माध्यमिक स्तर के गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के संसाधनों का अध्ययन करना।
(3) निजी विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में अन्तर का अध्ययन करना।

शोध विधि :–

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु अनुसंधान विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

शोध उपकरण :–

शोध प्रदत्तों के संकलन हेतु स्वनीर्मित प्रश्नावली प्रविधियों का उपयोग किया गया है।

शोध के चर –

- **स्वतंत्र चर** :–माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी
- **आश्रित चर** :–शिक्षा की गुणवत्ता

उद्देश्य –माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के निजीकरण से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव का अध्ययन।

क्र.सं.	श्रेणी	संख्या – छात्र व छात्राओं की	प्रतिशत
1.	छात्र	50	98.4%
2.	छात्रा	50	96.06%

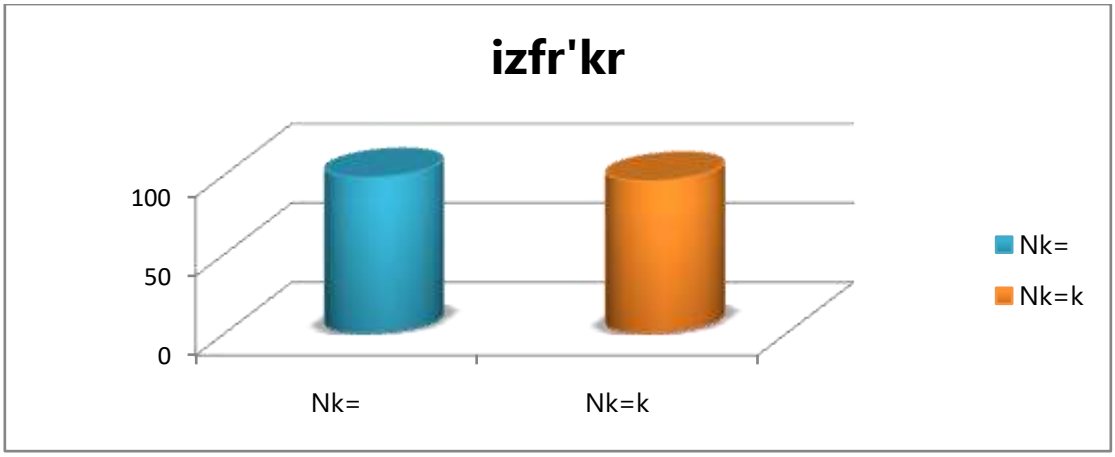

उद्देश्य –माध्यमिक स्तर के सहायता प्राप्त विद्यालयों के संसाधनों का अध्ययन करना।

क्र.सं.	श्रेणी	संख्या – छात्र व छात्राओं की	प्रतिशत
1ण	छात्र	50	97ण4:
2ण	छात्रा	50	96ण20:

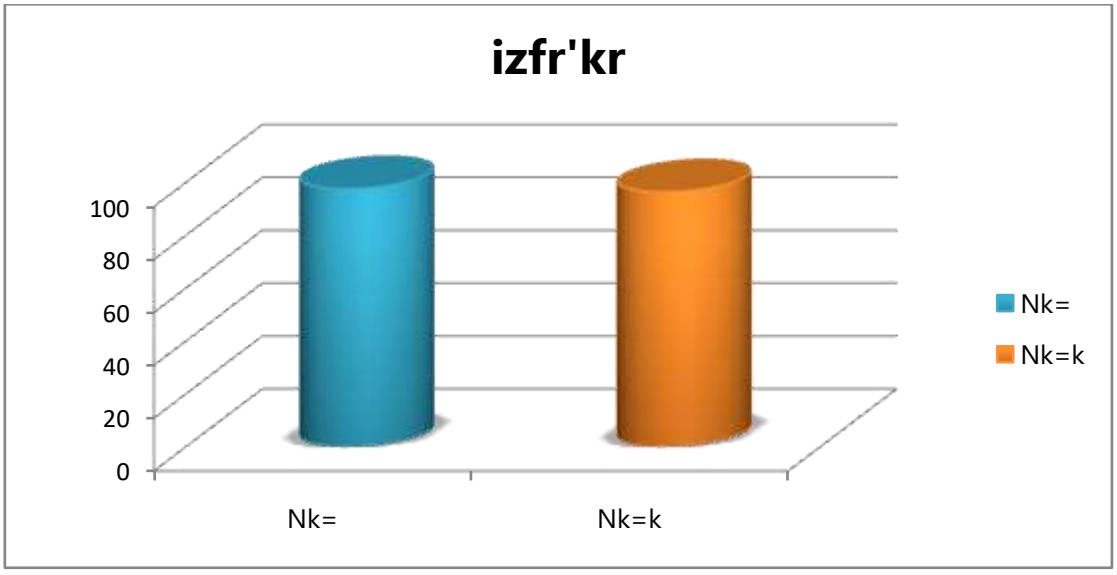

परिणाम

निष्कर्ष रूप में पाया गया कि माध्यमिक स्तर के सहायता प्राप्त विद्यालयों के संसाधनों का अध्ययन किया गया। क्योंकि उच्च माध्यमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अधिकार, समान वातावरण एवं समान अवसर प्रदान किये गये है एवं लिंग भेद के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। माध्यमिक स्तर के गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के संसाधनों का अध्ययन करना क्योंकि उच्च माध्यमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अधिकार,

समान वातावरण एवं समान अवसर प्रदान किये गये है एवं लिंग भेद के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया गया।

सन्दर्भ सूची

[1]. **अस्थाना, विपिन और अस्थाना, श्वेता (2007)** : "मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन" आगरा विनोद पुस्तक मंदिर आगरा.

[2]. **आचार्य बाड्मय पण्डित श्री राम शर्मा (1995)**''अपरिमित सम्भावनाओं का आगार, मानवी व्यक्तित्व'' खण्डज्योति।

[3]. **भटनागर, सुरेश, (2000)** ''शिक्षा मनोविज्ञान'', आर.लाल. बुक डिपो, मेरठ

[4]. **चौधरी, प्यारेलाल,(2008) ''**शैक्षिक अनुसंधान'', स्वाति पब्लिकेशन्स, जयपुर.

[5]. **गुडे व हॉट,(1995)**''मापन एवं मूल्याकंन'' ईगल बुक्स इंटरनेशलन, प्रकाशन मेरठ

[6]. **कपिल,डॉ. एच.के.(2007)** ''सांख्यिकी के मूल तत्व'', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा,

[7]. **मंगल, एस.के.,(2008)**''शिक्षा मनोविज्ञान'', प्रेन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया प्रा.लि., नई दिल्ली, संस्करण–

[8]. **मंगल, डॉ. अंशु, बरोलिया, डॉ. ए. अग्रवाल, श्रीमती नीतू, दुबे, श्री कृष्ण,(2002)** ''शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ, समंक विश्लेषण एवं शैक्षिक सांख्यिकी'', राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा.